

27 प्रतशित आरक्षण पर लगी रोक बरकरार, हाईकोर्ट ने अंतरमि आदेश में संशोधन से कथिा इनकार

चर्चा में क्यों?

23 जून, 2022 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीएससी (लोक सेवा आयोग) में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतशित आरक्षण देने पर लगी अंतरमि रोक के आदेश में संशोधन से इनकार कर दथिा ।

प्रमुख बढि

- ओबीसी आरक्षण के संबंध में दायर सभी याचकियाओं की सुनवाई जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस ए.के. शर्मा की युगल पीठ द्वारा की गई ।
- गौरतलब है कऱ आशतिा दूबे सहति अनूय की तरफ से प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण 27 प्रतशित कथिे जाने के खलिाफ तथा पक्ष में लगभग 60 से अधिक याचकियाँ दायर की गई थीं । हाईकोर्ट ने कई लंबति याचकियाओं पर ओबीसी आरक्षण 27 प्रतशित दथिे जाने पर रोक लगा दी थी ।
- सरकार द्वारा स्थगन आदेश वापस लेने के लथिे आवेदन दायर कथिा गया था । हाईकोर्ट ने 1 सतिंबर, 2021 को स्थगन आदेश वापस लेने से इनकार करते हुए संबंधति याचकियाओं को अंतमि सुनवाई के नरिदेश जारी कथिे थे ।
- प्रदेश सरकार के सामानूय प्रशासन वभिाग ने महाधविकता द्वारा 25 अगस्त, 2021 को दथिे अभमित के आधार पर पीजी नीट 2019-20, पीएससी के माध्यम से होने वाली मेडकिल अधिकारथिी की नथुकृति तथा शकषक भरती छोडकर अनूय वभिाग में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतशित आरक्षण दथिे जाने के आदेश जारी कर दथिे थे । उक्त आदेश के खलिाफ भी हाईकोर्ट में याचकिया दायर की गई थी ।
- आरक्षण के खलिाफ दायर याचकियाओं में कहा गया था कऱ सुप्रीम कोर्ट की संवैधानकि पीठ ने साल 1993 में इंदरिा साहनी तथा साल 2021 में मराठा आरक्षण के मामले में स्पष्ट आदेश दथिे हैं कऱ आरक्षण की सीमा 50 प्रतशित से अधिक नहीं होना चाहथिे । प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतशित कथिे जाने पर आरक्षण की सीमा 63 प्रतशित तक पहुँच जाएगी ।
- याचकिया की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से दायर जवाब में कहा गया था कऱ साल 2011 की जगगणना के अनुसार प्रदेश में ओबीसी वर्ग की संख्या लगभग 51 प्रतशित है । सुनवाई के दौरान पीठ से आग्रह कथिा गया था कऱ पीएससी में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतशित आरक्षण देने के संबंध में जारी अंतरमि रोक के आदेश को संशोधति कथिा जाए । पीठ ने आग्रह को अस्वीकार करते हुए उक्त आदेश जारी कथिे ।